P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-5* January- 2021
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का महाविलयः एक दृष्टि

Public Sector Banks in India: A Vision

Paper Submission: 15/01/2021, Date of Acceptance: 26/01/2021, Date of Publication: 27/01/2021

रामसुरेन्द्र यादव
सहायक प्राध्यापक,
वाणिज्य विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, मुसाफिरखाना
अमेठी, भारत

सारांश

भारत में बैंकों के राष्ट्रीकरण से पहले भारतीय पूँजी परपूँजीपतियों और औद्योगिक घरानों का ही नियन्त्रण था, उस समय बैंकों में जमा पैसों की सुरक्षा के लिए कोई गारंटी नहीं था, किन्तु आजादी के बाद जुलाई 1969 से बैंकों के राष्ट्रीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी जिसका मूल उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था में कृषि, लघु उद्योग और निर्यात पर अधिक ध्यान देना था, इसके साथ ही नये उद्यमियों और पिछड़े तबकों का विकास करना भी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों के प्रति जनता का विश्वास बढ़ने लगा और बैंकिंग व्यवसाय के अधिकांश भाग पर सार्वजनिक बैंकों का अधिकार हो गया। बैंक किसी अर्थव्यवस्था के केन्द्र बिन्दु होते हैं इसलिए अर्थव्यवस्था के अनुसार उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। जब दो या दो से अधिक बैंक आपस में मिलकर किसी एक नाम से बैंकिंग का कार्य करते हैं तो बैंकों के इस आपसी मिलन की प्रक्रिया को बैंकों का विलय कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बढ़ते एन0 पी0 ए0 तथा खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए समय–समय पर भारत सरकार द्वारा बैंकों के विलय का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में देश के वित मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 10 बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाने का निर्णय लिया गया। इस महाविलय के बाद अब भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल बैंकों की संख्या 27 से घट कर 12 हो गयी हैं। इस शोध पत्र में बैंको की स्थापना, राष्ट्रीकरण तथा वर्तमान में विलय तक के क्रमिक परिवर्तन का अध्ययन किया गया है तथा बैंकों के विलय के प्रभाव व चुनौतियों का आकलन भी हुआ है। इस शोध पत्र में द्वितीयक समंको का प्रयोग किया गया है।

Prior to the nationalization of banks in India, there was control of Indian capitalists and industrial houses, at that time there was no guarantee for the security of bank deposits, but after independence, the process of nationalization of banks started from July 1969. The objective was to pay more attention to agriculture, small scale industries and exports in the country's economy, besides developing new entrepreneurs and backward classes. After the nationalization of banks, public confidence in banks started to increase and most of the banking business became owned by public banks. Banks are the focal point of an economy, so it is bound to change according to the economy. When two or more banks work together in one name, the process of this mutual union of banks is called merger of banks. In view of the increasing NPA and poor financial condition in the public sector banks, the Government of India decided to merge the banks from time to time. In this sequence, it was decided by the country's Finance Minister Nirmala Sitharaman to merge 10 banks to form 4 big banks. After this Great Wall, the total number of public sector banks in India has come down from 27 to 12. In this research paper, the gradual changes up to the establishment, nationalization and present-day merger of banks have been studied and the impact and challenges of merger of banks have also been assessed. Secondary links have been used in this research paper.

मुख्य शब्द : सार्वजनिक बैंक, राष्ट्रीयकरण, अर्थव्यवस्था, विलय, एन0पी0ए0।
Public Banks, Nationalization, Economy, Mergers, N.P.A.

प्रस्तावना

देश में सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों के महाविलय के बाद 1 अप्रैल, 2020 से देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको की संख्या घटकर मात्र 12 रह गई

है। बैंकिंग क्षेत्र में ऐसा परिवर्तन कोई नया नहीं है बल्कि ऐतिहासिक काल से ही समय और अर्थव्यवस्था की माँग के अनुरूप इसके रूप एवं आकार में परिवर्तन होता रहा है, कभी बैंकों की संख्या बढ़ाने एवं विभिन्न क्षेत्रों में नए बैंकों की स्थापना को प्राथमिकता दी गई तो कभी बैंकों की संख्या में कमी करने का निर्णय लिया गया।

भारत में बैंकों का उदय 18वीं शताब्दी में हो चुका था। वर्ष 1770 में बैंक ऑफ हिंन्दुस्तान तथा वर्ष 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, बाद में ब्रिटिश शासन काल में देश में निम्न तीन प्रेसीडेंसी बैंकों की स्थापना की गयी–

1. बैंक ऑफ कलकत्ता (2 जून, 1806 कोलकाता में)
2. बैंक ऑफ बॉम्बे (15 अप्रैल, 1840 मुंबई में)
3. बैंक ऑफ मद्रास (1 जुलाई, 1843 चेन्नई में)

यह तीनों बैंक ब्रिटिश शासन काल के अधीन अर्द्धकेन्द्रीय बैंक के रूप में कार्य करते थे। 02 जनवरी , 1809 को बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल रखा गया। इन बैंकों को नोट निर्गमन एवं मौद्रिक नियंत्रण का भी अधिकार प्राप्त था, बाद में 27 जनवरी 1921 को इन तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया (भारत का शाही बैंक) की स्थापना की गई, इसे भी केन्द्रीय बैंक के कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। 1 अप्रैल, 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई जिसे केन्द्रीय बैंक का दर्जा दिया गया तथा 1 जनवरी, 1949 में इसका राष्ट्रीकरण कर दिया गया। 1921 में स्थापित इंपीरियल बैंक को 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में स्थापित किया गया तथा 1 जुलाई, 1955 को इसका राष्ट्रीकरण करके इसके केन्द्रीय बैंक के कार्य अधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा केन्द्रीय बैंक का समस्त कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया। बाद में भारतीय स्टेट बैंक के 7 और सहयोगी बैंकों की स्थापना की गयी और इस प्रकार इन आठों बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक समूह के नाम से जाना जाने लगा जो निम्न प्रकार हैं:–

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
3. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
4. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर
5. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
6. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
7. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
8. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

साहित्यावलोकन

डॉ0 शर्मा अंजली, 2020(द मेगा मर्जर 2020: एन इम्पीरिकल स्टडी–इण्टरनेशनल स्टडी आफ एडवांस रिसर्च इन कामर्स, मैनेजमेंट एण्ड सोशल साइंस, ISSN-2581-7930, वालूम 03, जनवरी–मार्च,2020): इस शोध–पत्र में बैंकों के विलय के कारणों व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के महाविलय का अध्ययन किया गया है, जिसके अन्तर्गत विलय का कारण बढ़ते एन. पी. ए. व खराब वित्तीय स्थिति को बताते हुए 10 बैंकों के महाविलय का विश्लेषण किय गया है।

डॉ0 ताज सदाफ, 2019 (एन इनवेस्टीगेशन आफ मर्जर इन इण्डियन बैंकिंग सेक्टर पोस्ट गवर्नमेन्ट्स एनाउन्समेंट ऑफ मेगा मर्जर इन 2019 फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स –EPRAइण्टरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट,ISSN-2455-7838, वालूम 04, अक्टूबर,2019) के इस अध्ययन में बैंकों के विलय से होने वाले लाभ व हानियों पर प्रकाश डाला गया है तथा विभिन्न चरणों में बैंकों के विलय का क्रमशः अध्ययन किया गया है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध पत्र विवरणात्मक प्रकृति का है जो बैंको के स्थापना व राष्ट्रीयकरण से लेकर विलय तक के तथ्यों पर प्रकाश डालता है। इसमें प्रयुक्त सूचनाएं द्वितीयक समंको पर आधारित हैं जो विभिन्न शोध, पत्र, पत्रिकाओं, ऑनलाइन साइटों, सरकारी गजट एवं संबंधित पुस्तकों से लिए गए हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

1. बैंको के स्थापना राष्ट्रीकरण एवं विलय प्रक्रिया के क्रमिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए।
2. विलय प्रक्रिया में प्रभावित होने वाले बैंकों तथा इसके उपरान्त सार्वजनिक क्षेत्र में बचे कुल बैंको को जानने के लिए।
3. बैंकों के विलय के उद्देश्य व प्रभाव को जानने के लिए।
4. बैंकों के विलय के फलस्वरूप आने वाली चुनौतियों के आकलन के लिए।

निजी बैंकों का राष्ट्रीकरण

19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैकों का तेजी से विकास प्रारम्भ हो चुका था जिनकी संख्या बीसवीं शताब्दी के मध्य तक 50 से अधिक हो गई किन्तु ये बैंक मुख्य रूप से व्यवसायिक क्रियाओं में ही मद्द करते थे। देश के समुचित विकास की अवधारणा के अन्तर्गत 19 जुलाई, 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी द्वारा ऐसे बड़े 14 निजी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीकरण किया गया जिनकी पूंजी ?50 करोड़ से अधिक थी। ये राष्ट्रीकृत बैंक इस प्रकार हैं:

1. इलाहाबाद बैंक
2. बैंक आफ बड़ौदा
3. बैंक ऑफ इंडिया
4. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
5. केनरा बैंक
6. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
7. देना बैंक
8. इंडियन बैंक
9. इंडियन ओवरसीज बैंक
10. पंजाब नेशनल बैंक
11. सिंडिकेट बैंक
12. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
13. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
14. यूनाइटेड कामर्शियल बैंक

इन बैंकों के राष्ट्रीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी तेजी देखने को मिली और बैंकिग व्यवसाय के 85 प्रतिशत पर इनका अधिकार रहा। कृषि एवं ग्रामीण वित्त व्यवस्था के लिए विशेष रूप से 02 अक्टूबर, 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की

गयी। बैंकों के राष्ट्रीकरण के प्रथम चक्र की सफलता को देखते हुए 15 अप्रैल, 1980 को ?200 करोड़ रूपये से अधिक जमा के साथ निजी क्षेत्र के 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीकरण किया गया जिनका विवरण निम्न है:

1. आंध्रा बैंक
2. कारपोरेशन बैंक
3. न्यू बैंक ऑफ इंडिया
4. ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स
5. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
6. विजया बैंक

इस प्रकार राष्ट्रीकृत वाणिज्यिक बैंको की संख्या 20 हई, निजी बैंको के राष्ट्रीकरण का यह अंतिम चरण था।

सार्वजनिकक्षेत्र के बैंकों का विलय

1980 के बाद किसी निजी बैंक का राष्ट्रीकरण नहीं हुआ बल्कि आगे चलकर धीरे–धीरे बैकों के विलय का चक्र प्रारम्भ हुआ जिसका अध्ययन निम्न प्रकार किया जा सकता है:

विलय,1993

सर्वप्रथम 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया यह विलय न्यू बैंक ऑफ इंडिया के निरंतर हानि में चलने के कारण उसके अंश धारियों की सुरक्षा के लिए किया गया था।

विलय,2008

भारतीय स्टेट बैंक समूह के सबसे छोटे सहयोगी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का 2008 में भारतीय स्टेट बैंक में विलय किया गया इस विलय से सहयोगी बैंको की संख्या 7 से घटकर 6 हो गयी।

विलय,2010

वर्ष 2010 में भारतीय स्टेट बैंक समूह के एक और बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय किया गया जिससे सहयोगी बैंकों की संख्या घटकर 5 रह गई।

विलय,2017

वर्ष 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के शेष पॉचो एसोसिएट बैंको का भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया साथ ही महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए 19 नवम्बर, 2013 में स्थापित भारतीय महिला बैंक का भी विलय भारतीय स्टेट बैंक में किया गया।

विलय,2019

1 अप्रैल, 2019 को सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों–देना बैंक और विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय किया गया तथा इसकी सफलता के आधार पर एक महाविलय की भी घोषणा की गयी।

महाविलय,2020

2019 के विलय के अच्छे परिणाम आने के बाद दिसम्बर 2019 में भारत के वित्त मंत्री द्वारा सरकारी बैंको के महाविलय की घोषणा की गई थी। सरकार का मानना है कि वर्तमान समय में छोटे–छोटे अधिक बैंकों की आवश्यकता नहीं है बल्कि बड़े आकार के कुछ ही बैंकों की आवश्यकता है जिससे इन बैंकों की आपसी प्रतियोगिता समाप्त होगी, वहीं एन0 पी0 ए0 में भी कमी आएगी साथ ही सरकार द्वारा इन बैंकों की वित्त व्यवस्था आसानी से की जा सकेगी। इसी क्रम में 6 बैंकों– सिंडीकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कारपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक एवं इलाहाबाद बैंक का विलय केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं इंडियन बैंक के साथ कर दिया गया है:

बैंक	विलय हुए बैंक
केनरा बैंक	सिंडीकेट बैंक
पंजाब नेशनल बैंक	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	कारपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक
इंडियन बैंक	इलाहाबाद बैंक

इन 10 बैंकों के महाविलय के बाद अब देश में 1 अप्रैल, 2020 से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या मात्र 12 रह गयी है। इन 12 बैंकों की सूची निम्न है:

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के नाम (सरकार की हिस्सेदारी)

बैंक	सरकार की हिस्सेदारी प्रतिशत में
स्टेट बैंक इंडिया	61.00
बैंक आफ बड़ौदा	63.74
केनरा बैंक	72.55
पंजाब नेशनल बैंक	70.22
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	67.43
इंडियन बैंक	81.73
पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक	79.62
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	87.01
बैंक ऑफ इंडिया	87.0535
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	88.02
इंडियन ओवरसीज बैंक	91.00
यूको बैंक	93.29

बैंकों के विलय का उद्देश्य एवं प्रभाव

बैंकों का विलय जिस उद्देश्य से किया जा रहा है इसका प्रभाव आने वाले कुछ समय के बाद ही पता चल सकेगा किन्तु इसका आकलन हम निम्न बिंदुओं से कर सकते हैं।

1. बैंकों के विलय के फलस्वरूप बैंकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
2. बैंकों के कर्ज देने की क्षमता में वृद्धि होगी।
3. देश के अंदर बैंको के आंतरिक प्रतियोगिता में कमी आएगी तथा बैंक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सक्षम होंगे।
4. सरकार को बैंकों की आर्थिक मदद करने में आसानी होगी।
5. बैंकों के बढ़ते एन0पी0ए0 तथा खराब ऋणों के वितरण को नियंत्रित किया जा सकेगा।
6. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा मानना है कि एक अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए किसी देश में 5 से 10 बड़े बैंक होने चाहिए।

7. केन्द्र सरकार के वर्ष 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन करने के लक्ष्य में मदद मिलेगी।
8. अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने में मदद मिलेगी।
9. बैंकोंके एकीकरण से उनकी परिचालन लागत कम होगी।
10. बैंकोंके एकीकरण से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी जिससे वे सस्ता एवं ज्यादा मात्रा में कर्ज बाँट सकेंगे।
11. बैंकों की पहुँच नये राज्यों व क्षेत्रों तक हो जाएगी।
12. बैंक नई तकनीक और विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
13. बैंकों के विलय के उपरान्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कम रहेगी जिससे उन पर सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण मजबूत होगा।

बैंकों के विलय की चुनौतियाँ

यद्यपि बैंकों का समेकन अर्थव्यवस्था को गति देने एवं अन्य विभिन्न दृष्टिकोण से आवश्यक समझा जा रहा है किंतु समेकन की प्रक्रिया एवं इसके परिणाम स्वरूप चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं जिसे निम्न विंदुओं द्वारा समझा जा सकता है।

1. सभी बैकों के काम करने की तकनीक एवं सॉफ्टवेयर का वर्जन अलग–अलग रहता है इन्हें एक साथ समायोजित करना एक बड़ी चुनौती होगी।
2. मानव संसाधन बैंकों के एकीकरण की बड़ी चुनौती है क्योंकि अलग–अलग बैंको में मानव संसाधन नीतियाँ अलग–अलग होती हैं तथा उनके काम करने की दशाएं भी अलग होती हैं ऐसी दशा में मानव संसाधन नीतियों का एकीकरण तथा कर्मचारियों की छँटनी आदि से संबंधित समस्याएं आएंगी।
3. बैंक अलग–अलग नेटवर्क में काम करते हैं बैंकों के मर्जर के साथ ही उनके नेटवर्कों का मर्जर भी करना पड़ेगा जो कि एक मुश्किल काम होगा।
4. यदि किसी स्थान पर समेकित होने वाले दोनों बैंको की शाखाएं हैं तो उसमें से किस शाखा को अन्यत्र शिफ्ट किया जायेगा अथवा बंद किया जायेगा यह समस्या आएगी।
5. एक ही स्थान पर विलय होने वाले दोनों बैंको के ए.टी. एम. होने पर उसमें भी यही समस्या आएगी कि किस एटीएम को बंद किया जायेगा।
6. अलग–अलग बैंकों के ग्राहकों को एक साथ समायोजित करना एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि उनके पासबुक से लेकर ए.टी.एम. कार्ड तक बदलने होंगे साथ ही ग्राहकों की संतुष्टि स्तर को भी बनाए रखना होगा।
7. विलय के बाद बैंकों के एन0 पी0 ए0 की समस्या सुलझ जायेगी या न वापिस होने वाले ऋणों पर नियन्त्रण लगेगा यह एक बड़ी चुनौती होगी।
8. भारत पहले से ही बेराजगारी की समस्यासे जूझ रहा है ऐसे में इस पर विलय का क्या प्रभाव पड़ेगा।
9. विलय होने वाले बैंकों की बैलेंस शीट को समेकित करना होगा साथ ही उनके पास जमा सभी धन को भी इकट्ठा करना होगा।
10. अधिक एन0 पी0 ए0 वाले बैंकों के साथ मर्जर होने वाले मजबूत स्थित वाले बैंकों के संचालन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

निष्कर्ष

भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वित्तीय स्थिति मजबूत करने एन0 पी0 ए0 तथा खराब ऋण वितरण पर रोक लगाने, सस्ते ऋण उपलब्ध कराने तथा बैंको की पहुँच सभी राज्यों व क्षेत्रों तक करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंको के एकीकरण का निर्णय लिया गया है। इस महाविलय के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के महाविलय के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको की संख्या घटकर संख्या मात्र 12 रह जायेगी। इस महाविलय से जहाँ बैंकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तथा उनके ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होगी। वहीं उनके सामने मानव संसाधन,नेटवर्किंग समायोजन, ग्राहको के समायोजन तथा बेरोजगारी को लेकर बड़ी चुनौतियाँ भी हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *डॉ0 शर्मा अंजली, 2020 (द मेगा मर्जर 2020: एन इम्पीरिकल स्टडी–इण्टरनेशनल स्टडी आफ एडवांस रिसर्च इन कामर्स, मैनेजमेंट एण्ड सोशल साइंस, ISSN-2581-7930, वालूम 03, जनवरी–मार्च, 2020)*
2. *डॉ0 ताज सदाफ, 2019 (एन इनवेस्टीगेशन आफ मर्जर इन इण्डियन बैंकिंग सेक्टर पोस्ट गवर्नमेन्ट्स एनाउन्समेंट ऑफ मेगा मर्जर इन 2019 फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स –EPRA इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट, ISSN-2455-7838, वालूम 04, अक्टूबर,2019)*
3. *Ishwarya J (2019), A Study on Mergers and Acquisition of Banks and a Case Study on SBI and its Associates,(ISSN: 2394-9333)*
4. *Naveen Kumara, Vidhya VJ and Meghana B Reddy (2019), A Study on the Impact of Pre and Post BankMerger Aannouncement on Stock Price Movements, (E-ISSN 2348-1269, P- ISSN 2349-5138)*
5. *Prof. Sandep M. Khan Walker and Dr. Ashulekha gupta-merger of public sector banks in india :synergies at work.*
6. **भारतीय बैंकिंग प्रणाली डॉ बी सीसिन्हा**
7. *https://m.businesstoday.in/lite/story/10-public-sector-banks-to-merge-into-4-today-all-you-need-to-know/1/399792.html*
8. *https://www.moneycontrol.com/news/business/economy/mega-merger-of-psu-banks-to-be-effective-from-today-6-banks-cease-to-exist5094051.html/amp*
9. *https://m.rbi.org.in/Scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=931#*
10. *https://en.m.wikipedia.org/wiki/Narasimham_Committee*
11. *https://en.m.wikipedia.org/wiki/Public_sector_banks in India*
12. *Times of india business*
13. *https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/mega-merger-of-10-psu-banks-takes-effect-things-to-know/articleshow/74935351.cms*
14. *https://hindi.bankersadda.com/2020/04/list-of-public-sector-banks.html*
15. *www.rbi.org.in*